॥ ओ३म् ॥
वेद प्रचार, विश्व शान्ति, राष्ट्रोत्थान एवं सम्पूर्ण क्रान्ति के लिये समर्पित पाक्षिक पत्र

आर्य नीति

कृण्वन्तो विश्वमार्यम

पाक्षिक

वर्ष : 19 अंक : 6 25 मार्च 2019 मूल्य एक प्रति : 3 रुपये डाक पंजियन संख्या : Jaipur City/264/2018-20 वार्षिक मूल्य : 100 रुपये

सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद एवं राजधर्म पत्रिका का स्वर्ण जयंती समारोह सम्पन्न

स्वर्ण जयंती समारोह के बाद आर्य जगत में क्रांतिकारी परिवर्तन की आशा

अब युवा शक्ति आर्य जगत का सूत्रधार बने

–सत्यव्रत सामवेदी

जयपुर 23 मार्च। सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद एवं राजधर्म पत्रिका का स्वर्ण जयंती समारोह 9 व 10 मार्च 2019 को स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम, टिटोली, रोहत के प्रांगण में अत्यंत उत्साह के साथ सम्पन्न हुआ।

इस समारोह में सम्मिलित होने की मेरी अदम्य कामना थी परंतु मैं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इस समारोह में उपस्थित नहीं हो सका, जिसका मुझे खेद है। इस समारोह में मुझे आर्य जगत को भारतवर्ष का सशक्त संगठन बनाने के लिए कुछ परामर्श देने थे, जिन्हें मैं इस लेख के माध्यम से दे रहा हूँ।

ध्वजारोहण करते हुए सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कोषाध्यक्ष पं. माया प्रकाश त्यागी जी, सभा प्रधान स्वामी आर्यवेश जी, स्वामी आगनेश जी, स्वामी धर्ममुनि जी, स्वामी विजयवेश जी, स्वामी देवेश्वरानन्द जी, श्री गोविन्द सिंह भण्डारी, डॉ. लक्ष्मणदास आर्य जी, श्री लाजपत राय चौधरी जी, श्री कमल आर्य जी, श्री चाँदमल आर्य जी, श्री दयाकृष्ण काण्डपाल जी, प्रो. आनन्द सिंह जी

एक समय था जब परतंत्र भारत में प्रत्येक भारतवासी को आर्य समाज का पांचजन्य सुनाई देता था। ऐसा लगता था कि भारत के कोने-कोने में ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया है और ब्रिटिश साम्राज्य इस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो जाएगा। प्रत्येक भारतवासी को आशा थी कि देश स्वतंत्र होगा तो आर्य समाज के युवकों के बलिदान से ही होगा।

सारे विश्व को आश्चर्य है कि आर्य समाज अभी तक भी जीवित कैसे है? आर्य समाज के कुछ आलोचक ही नहीं अपितु आर्य समाज के नेता भी मंचों से यह भाषण देने लगे हैं कि आर्य समाज एक जिंदा लाश है। इसकी ऊर्जा पूर्णतया समाप्त हो गई है। आज आर्य समाज पूर्णतः अप्रासंगिक हो चुका है। आर्य समाज इस स्थिति में कैसे पहुंचा?

आर्य समाज का आज भी जो अस्तित्व है उसकी जड़ों में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द, पंडित लेखराम, शेर-ए-पंजाब लाला लाजपत राय, सरफरोशी की तमन्ना के अमर गायक पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, 23 वर्ष 5 महिने 26 दिन के युवक शहीद-ए-आजम भगतसिंह का खून है। इन्हीं बलिदानियों का खून आर्य समाज के वृक्ष को हरा-भरा रखा हुआ है।

यह सर्वविदित तथ्य है कि जब भी किसी देश में क्रांति आई है वह नवयुवकों के कारण। जब विश्व की महान शक्ति रावण को पराजित करने के लिए राम निकले तब वे युवा थे, जब महाभारत के संग्राम में योगीराज कृष्ण ने पांचजन्य फूंका था तब वे युवक थे, जब शंकराचार्य दिग्विजय करने निकले तब वे 26 वर्ष के युवा थे, विश्व में वैदिक दुंदुभि बजाने का बीजारोपण महर्षि दयानन्द ने 16 वर्ष की अवस्था में हो गया था और धार्मिक तथा राजनीतिक क्रांति के लिए जब उन्होंने भारत के प्रांगण में प्रवेश किया तब वे 28 वर्ष के थे और महर्षि ने समस्त मतमतान्तरों की छातियों को अपने तर्कबाण से विदीर्ण कर दिया और उनकी प्रेरणा से ही लाखों युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। स्वामी विवेकानन्द ने भी सारे विश्व में वैदिक संस्कृति की जब धूम मचाई थी तब वे 28 वर्ष के थे।

आर्य समाज के निरंतर पतन का कारण यही है कि इस संगठन में वृद्धों का वर्चस्व बढ़ता गया और धीरे-धीरे युवा शक्ति को संगठन से बाहर निकाल दिया गया।

अगर हम चाहते हैं कि आर्य समाज अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करे तो युवा शक्ति को आगे आना पड़ेगा। आर्य जगत में केवल एक ही संन्यासी ऐसा है जो युवा शक्ति को आगे लाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है और उसका नाम है स्वामी आर्यवेश।

मेरी यह अदम्य कामना है कि स्वामी आर्यवेश जी के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी युवा शक्ति खड़ी हो और हर भारतवासी की जबान पर आर्य समाज का नाम हो। ऐसी बात नहीं है कि गत 50-60 वर्षों में आर्य समाज का कोई काम नहीं हुआ। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के तत्वावधान में अनेक सम्मेलन हुए और हरेक सम्मेलन में यह आशा जाग्रत हुई कि आर्य जगत में नया मोड़ आयेगा।

इस लेख के माध्यम से मैं स्वामी आर्यवेश जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर आंदोलन के लिए युवकों को प्रेरित करें।

अनेक मुद्दे ऐसे हैं जिनपर सारा भारतवर्ष चिंतन करता है। इन मुद्दों को लेकर अगर 100-200 युवा भी सड़कों पर आ जाएं तो सारा भारत उनका यशोगान करेगा। जो काम अनेक वर्षों के अनथक प्रयास से पूरे नहीं होते वे सही मुद्दों पर सही कदम उठाने से एक दिन में हो सकते हैं। अतः आर्यवेश जी को दिल्ली में कम से कम 100 नवयुवकों का संगठन बनाना चाहिए जो उनकी आवाज पर उपस्थित होने के लिए तैयार हो। इन 100 नवयुवकों का प्रदर्शन पूरी दिल्ली में हो और संसद पर या प्रधानमंत्री अथवा सम्बन्धित मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन किया जाए और प्रधानमंत्री तथा संबंधित मंत्री को सार्वदेशिक सभा का ज्ञापन दिया जाए। इसी प्रकार प्रांतीय या राष्ट्रीय स्तर पर भी 100 नवयुवकों का संगठन हो। 10-10 नवयुवकों के संगठन हो जो अपने खर्चे पर एक महिने में एक सप्ताह देने के लिए तैयार हों। ऐसे 10 संगठन अपनी जीप और भोजन आदि की व्यवस्था करें। दस जीपें 100

नवयुवकों के साथ शहर के बाजारों में रैली निकालें और नारे लगाएं तथा नुक्कड़ सभाएं करें। जिस शहर में यह आयोजन किया जाये वहां प्रेस कांफ्रेंस की जाए और आर्य समाज के मंतव्यों की जानकारी पत्रकारों को दी जाए।

भारतवर्ष में ऐसी अनेक आर्य समाजें हैं जो 10 नवयुवकों के जीप और भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। 10-10 युवकों के दो संगठन राजस्थान में तैयार किये जा सकते हैं। मेरा आग्रह है कि राष्ट्रभक्ति से अनुप्राणित 100 नवयुवकों का दो दिन का सम्मेलन आर्य समाज, आदर्श नगर, जयपुर में आयोजित किया जाये।

आज विश्व का स्वर्ग काश्मीर जल रहा है। भारतवासी को यह मालूम ही नहीं कि काश्मीर की रक्षा 1947 में कट्टर आर्य समाजी श्री मेहरचन्द महाजन ने की थी। कबायली लोग श्रीनगर की सीमाओं तक पहुंच चुके थे। महाज़न साहब ने सरदार पटेल को फोन कर सेना भेजने के लिए आग्रह किया तब काश्मीर भारत का अंग बन सका परंतु काश्मीर की समस्या का समाधान जिन नेताओं पर छोड़ा गया उन्होंने इस समस्या को हमेशा के लिए उलझा दिया और आज काश्मीर आतंकवाद के ज्वालामुखी में जल रहा है। काश्मीर में 370 धारा लगा कर काश्मीर को भारतवर्ष से एक प्रकार से अलग कर दिया गया।

धरती का स्वर्ग कश्मीर जल रहा है। आज से नहीं पिछले 72 सालों से। पिछले तीन दशकों में ही 41 हजार से ज्यादा लोग इस स्वर्ग में आतंकवाद से स्वर्गवासी हो गए। भारतीयों को तो इस स्वर्ग में रहने का अधिकार ही नहीं है लेकिन जो कश्मीरी वहां रह रहे हैं, उनकी जिन्दगी कम नारकीय नहीं है। ऐसे में पुलवामा के जवाब में हुई एयर स्ट्राइक की घटना मात्र से सारे देश में हर्ष की लहर दौड़ गई। यह लहर इस बात कासंकेत भी है कि कश्मीर को लेकर भारतवासियों के दिलों में दर्द कितना गहरा है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या कश्मीर के हालात सुधारने के लिए यह दवा काफी है? जवाब आएगा, नहीं। इसे वापस स्वर्ग बनाने के लिए धारा-370 और 35 ए जैसे कांटों को हटाना जरूरी है।

कश्मीरी मुसलमानों में अलगाव और आतंकवाद की जड़ संविधान की अस्थायी धारा-370 है। पं. नेहरू ने शेख अब्दुल्ला के आग्रह पर यह धारा स्वीकार की थी। अब्दुल्ला कश्मीर के भारत में विलय के पक्षधर नहीं थे। उन्होंने कहा था 'हमने कश्मीर का ताज खाक से उठाया है। हम हिन्दुस्तान में शामिल होंगे या पाकिस्तान में यह बाद का प्रश्न है। पहले हमें अपनी आजादी मुकम्मल करनी है।' इतना ही नहीं उनका यह कहना भी था कि वे केन्द्रीय सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें हिन्दुओं का बहुमत होगा। मुस्लिमों को आश्वस्त करने के लिए कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाए। उसका अपना झण्डा, सदर-ए-रियासत और संविधान हो। इस प्रस्ताव का संविधान सभा ने विरोध किया था, किन्तु नेहरू के 'वचन' के कारण स्वीकार कर लिया गया। बाद में गोपालस्वामी ने कहा था कि यह धारा अस्थायी है। इसे शीघ्र ही निरस्त कर दिया जाएगा।

आज यह धारा भारत की एकता के लिए चुनौती बन चुकी है। दो दिन पहले ही वहां की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कह दिया कि धारा हटाने की कोशिश हुई तो लोग पता नहीं कौन सा झण्डा उठा लेंगे। इनके पिता की राष्ट्रभक्ति पूरा देश देख चुका है। इनके आगे देश बहुत तुच्छ वस्तु है। अब तो केन्द्र सरकार ने भी मान लिया होगा कि उसने भी सांपों को ही दूध पिलाया था। इनको ऐसी धारा चाहिए जो पंथ निरपेक्षता और संविधान के मूल सिद्धांतों को ठुकरा दे। समान नागरिक अधिकारों का सम्मान न करें। कश्मीर के नागरिकों को पूरे देश में समान अधिकार प्राप्त हों, किन्तु भारतवासियों को कश्मीर में रहने-करने का, शादी करने-कराने का, सम्पत्ति खरीद का अधिकार न हो। हां, यहां की स्त्रियां पाकिस्तानी पुरुष के साथ शादी करके उन्हें कश्मीर का नागरिक बना सकती हैं।

कश्मीर का संविधान और राष्ट्रध्वज अलग है। विस्थापित नागरिक सांसद चुन सकते हैं, विधायक नहीं। संसद को भी अत्यन्त सीमित क्षेत्रों के अधिकार प्राप्त हैं। उच्चतम न्यायालय के आदेश वहां मान्य नहीं है। अक्टूबर 2015 में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एच.एल. रत्तू ने धारा-370 हटाने वाली याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया था। उनका कहना था कि इस बारे में संसद ही फैसला कर सकती है। जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने इसे स्थायी प्रावधान ठहराते हुए कहा था कि इससे कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता।

ये सारे प्रयास देश और कश्मीर के रिश्तों को कमजोर करने के ही हैं। आज का वातावरण संविधान के प्रति सम्मानजनक कहां है? राजनीतिक इच्छाशक्ति कई बार उन्हीं का साथ देती जान पड़ती है। बौद्धिक स्तर पर हमार कार्रवाइयां भले ही सही जान पड़े, भारतीय जनभावनाओं का प्रभाव या दर्द निर्णयों में नहीं होता। सन् 1964 की संसद की बहस में, जो दस घंटों से अधिक चली, सभी ने स्पष्ट रूप से 370 की अस्थायी प्रकृति एवं उसके दुष्परिणामों के कारण इसे हटाने को कहा था। पूरी संसद एकमत थी। ढाई महीने में तीन बार बहस हुई थी। निर्णय नहीं हो पाया। आज तक भी नहीं हो पाया। सब अपने-अपने शब्दों से देश को भ्रमित करते जा रहे हैं।

कानूनी दोगलेपन का दूसरा प्रमाण है आर्टिकल 35-ए। संविधान में इसकी कहीं चर्चा नहीं है। बाद में 370 का ही उप-प्रावधान बनाया गया, जो कहता है कि राष्ट्रपति के आदेश से आप विशेष प्रावधान जम्मू-कश्मीर के लिए सम्मिलित कर सकते हैं। यह संविधान का विधायी प्रावधान नहीं है। इसी के अन्तर्गत वहां के स्थायी निवासी को जमीन, रोजगार आदि देने के अधिकार वहां की विधानसभा को हैं। समस्या की बड़ी जड़ बन गया है 35-ए। वहां के नागरिकों को दोहरी नागरिकता तथा भारतीय नागरिकों पर निषेध। सन् 1947 के बाद बसे प्रवासी भारत के नागरिक हैं, लोकसभा चुनाव में वोट डाल सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के स्थायी निवासी नहीं होने के कारण विधानसभा चुनावों में भाग नहीं ले सकते। वह भी उस अनुच्छेद के अन्तर्गत जो अभी भी संविधान का स्थायी अंग नहीं है। अधिकांश लोगों को तो शायद यह जानकारी भी नहीं होगी। सोच सकते हैं कि अनुच्छेद-370 किसके विरुद्ध है।

भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कश्मीर से धारा-370 हटाने का वादा किया था। सन् 2014 के चुनावों में तो भाजपा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र तक में धारा-370 हटाने की बात कही थी।

धारा-370 के प्रावधान में स्पष्ट कहा गया था कि जैसे ही जम्मू-कश्मीर का संविधान बनाने वाली समिति अपना कार्य शुरू करेगी, धारा-370 हट जाएगी। इस समिति को संविधान तथा विलय सम्बन्धी धाराएं तय करनी थीं। उसमें कहा गया कि अगर बीच में कभी धारा-370 को हटाना है तो इस समिति की अनुमति लेनी होगी। अपना कार्य पूरा करके संविधान समिति 1953 में भंग हो गई।

प्रश्न यह है कि क्या एक देश में दो विधान हो सकते हैं? तब धारा-370 क्यों? इसी के कारण आज वहां सारा विध्वंस हो रहा है। क्या राष्ट्रपति स्वयं अनुच्छेद-370 को नहीं हटा सकते? मोदी सरकार के पहले दिन ही राज्यमंत्री जितेन्द्र सिंह ने धारा-370 को नुकसानदायक बताया था। वे स्वयं जम्मू से हैं। आज चर्चा का एक बड़ा विषय यह भी बन गया है कि बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) से जो मुस्लिम आए, वे तो नागरिक बन सकते हैं लेकिन भारत के लोग जम्मू-कश्मीर में नहीं बस सकते। यही हमारी अखण्डता और पंथ निरपेक्षता का प्रमाण है। क्या यह शर्म की बात नहीं कि इस धारा के कारण भारत का कोई भी कानून जम्मू-कश्मीर में तभी लागू होगा, जब वहां की विधानसभा उसे पारित कर दे? न तो राष्ट्रपति इस राज्य के संविधान को रद्द कर सकते हैं, न ही कोई निर्देश दे सकते हैं। राष्ट्रपति की राष्ट्रीय संकट की घोषणा भी एक सीमा तक ही लागू हो सकती है।

समय के साथ वहां स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। सेना पर पथराव का एक बड़ा लम्बा दौर देश ने साक्षात किया। लोग बेरोकटोक आना-जाना चाहते हैं, घाटी में दोनों देशों की मुद्राएं प्रचलित हैं। अनेक प्रमुख नेताओं के पाकिस्तान में सीधे सम्पर्क भी हैं। पीडीपी स्व-शासन की बात करती है, कोई 1953 पूर्व, तो कोई आजाद कश्मीर की मुहिम चलाए हुए है। पाकिस्तान घाटी से सेना हटाने की मांग दोहराता रहता है। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को समाप्त करने का मुद्दा उठता रहता है। इसमें प्रावधान है कि किसी सैनिक के विरुद्ध अभियोग चलाने से पूर्व केन्द्र सरकार की स्वीकृति आवश्यक है। आज यह एक्ट भी निष्प्रभावी हो गया है। सरकारें सदा इन अलगाववादियों के आगे बहाने बना-बनाकर घुटने टेकती जाती हैं।

मैंने जनमानस की टोल लेने की दृष्टि से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की यात्रा की। राज्य में चल रहे कश्मीरी पंडितों और 1947 के बाद शरणार्थियों के शिविरों का भी दौरा किया। वहां साम्प्रदायिक स्वरूप प्रशासन में भी गहराता जा रहा है। आज विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन तक इस तरह हो चुका है कि केवल कश्मीर के क्षेत्र पर आधिपत्य जमाकर सरकार चलाई जा सकती है। इस प्रभाव को जम्मू की ओर बढ़ाने के प्रयास भी बदस्तूर जारी देखे थे।

हालात बदल चुके हैं। पुलवामा के हादसे ने जन-चेतना को जाग्रत कर दिया है। लोग प्रतिक्रिया करने लगे हैं। देश में बसे कश्मीरी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं। राज्य सरकारों को भी छात्रों की सुरक्षा के लिए विशेष निर्देश जारी हो चुके हैं। इसकी आंच जम्मू-कश्मीर के नेताओं तक भी पहुंच चुकी है। डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने और महबूबा मुफ्ती ने लौटने वाले प्रदेशवासियों के लिए मस्जिद-गुरुद्वारों में लंगर खोल दिए हैं। पुलिस के पहरे में लोगों को अपने शहरों तक पहुंचाया जा रहा है। यह सब काफी नहीं है।

न सर्जिकल स्ट्राइक ही काफी है। यह बुद्धिजीवियों को संतुष्ट करने का माध्यम जरूर है, किन्तु जनभावना के आहत मन का मरहम नहीं हो सकती। यह इस बात का संकेत भी है कि अभी सरकार भी स्थायी समाधान नहीं चाहती। युद्ध भी समाधान नहीं है। समाधान के लिए तोपहले आर्टिकल-35 ए को तुरन्त निरस्त करना पड़ेगा। यह दोगलेपन को लागू करने का प्रभावी हथियार है। साथ ही सरकार अनुच्छेद-370 को हटाने की सार्वजनिक घोषणा करके क्रियान्वयन प्रक्रिया शुरू कर दे। जनभावना को सत्ता के जोर से दबाया तो जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता।

(शेष पृष्ठ 6 पर)

23 मार्च : भगतसिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस

शोषित, पीड़ित समाज को समानता के अधिकार के पक्षधर थे भगतसिंह

शहीदों के शहीद कवि ओमप्रकाश की ये पंक्तियां उन दिनों घर-घर में गाई जाती थीं-

कभी वो दिन भी आयेगा कि आजाद हम होंगे,
ये अपनी ही जमीं होगी, यह अपना आसमां होगा।
शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले,
वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशां होगा॥

लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्त जब स्पेशल मजिस्ट्रेट की अदालत में आकर खड़े हुए तो लगा, इतना बड़ा देश हिन्दुस्तान सचमुच एक है। भारत माँ के निराले मतवाले सपूत सचमुच एक होकर माँ की बेड़ियां तोड़ने के लिए कटिबद्ध हैं। भगतसिंह, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, राजकुमार, विजयकुमार सिन्हा, जितेन्द्र सान्याल, जयदेव कपूर, आशाराम, महावीर सिंह, कमलनाथ तिवारी, किशोरी लाल, शिववर्मा, गयाप्रसाद, सुरेन्द्र पाण्डे, अजय घोष, कुन्दनलाल, देशराज और प्रेमदत्त-सभी तो सिर से कफन बांध कर माँ को आजाद कराने निकले थे। आजादी के दिवाने-क्रांति के राजदूत।

जैसे अखाड़े में मस्त पहलवान जाते हैं, उसी तरह क्रांति के ये दीवाने अदालत में आते थे। आते ही एक बार चारों ओर देखते, फिर नारा लगाते- इन्कलाब जिन्दाबाद। इसके बाद राष्ट्रीय गान आरंभ होता-वन्दे मातरम्...। उसके बाद झूमकर गाते-

सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है॥
वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां,
हम अभी से क्या बतायें क्या हमारे दिल में है।
ऐ शहीद मुल्कों मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार,
अब मेरी हिम्मत की चर्चा गैर की महफिल में है,
सर फरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।

फिर नारा गूंज उठता-इन्कलाब जिन्दाबाद। मजिस्ट्रेट कृष्ण वर्मा काला मुंह किये बैठा रहता और मौत के ये दीवाने झूम-झूम कर गाते रहते।

सरकार के अत्याचारों से तंग आकर इस मुकदमें में सरकारी गवाहों की पूरी पलटन तैयार हो गई थी। सरकार चाहती थी कि गवाहों की गवाहियों से वह इन लोगों को *जनता की निगाहों में सिरफिरा* और खूनी साबित कर दे, लेकिन परिणाम उल्टा हो रहा था। भगतसिंह ने इस तरह की व्यूह रचना की थी कि सरकार उसमें फंसती जा रही थी और जनता का झुकाव भगतसिंह और उनके साथियों की ओर होता जा रहा था।

जब सरकारी गवाह फणीन्द्रनाथ घोष कठघरे में आकर दल के भेद खोलने लगे तो शिव वर्मा ने इस सफाई से जिरह की कि उन्हें भरी अदालत में बम बनाने का फार्मूला और तरीका बताना पड़ गया। इस तरह नई पीढ़ी को बम बनाना आ गया।

श्रीमती सुभद्रा जोशी के शब्दों में उस समय का एक दृश्य प्रस्तुत है, 'न्यायाधीश के कमरे में न्यायाधीश ज्यों ही कुर्सी पर आकर बैठते, वह राष्ट्रीय गीतों और नारों से गूंज उठता। चारों ओर सन्नाटा छा जाता, न्यायाधीश सिर झुकाए कुर्सी पर मौन बैठे रहते, वकील एकदम मौन हो, अपने स्थान से हिलते तक न थे। अर्दली, सिपाही और दूसरे कर्मचारी भी सिर झुकाए खड़े या बैठे रहते थे। अभियुक्तों के सम्बन्धियों पर एक विचित्र-सी गंभीरता छा जाती थी। भगतसिंह और उसके साथी अदालत में पूरी तरह से छा जाते थे। सारा कमरा ही बलिदान के रंग में रंग जाने का दृश्य उपस्थित करता था।'

सुश्री वीरेन्द्र सिन्धु ने लिखा है- यह अदालत उन दिनों लाहौर की सबसे दिलचस्प जगह थी। अदालत का मुख्य द्वार बिल्कुल सड़क पर था। कॉलेजों-स्कूलों के विद्यार्थी छुट्टी होते ही दौड़ कर वहां आ जाते थे और इस तरह अदालत के बाहर भी अच्छी-खासी भीड़ जुट जाती थी। भगतसिंह खूब जोर से बोलते थे कि आवाज बाहर तक पहुंचे। जब अभियुक्त भीतर के कमरे में गाते थे तो बाहर खड़े लोग गाने लगते थे।

और इस तरह मुकदमे का नाटक चलता रहा। अचानक एक दिन मस्ती भरा यह वातावरण क्रोध के तूफान में बदल गया। मौत के ये दीवाने, क्रांति के ये अग्रदूत, जिनके होंठों पर हमेशा मुस्कान तैरा करती थी, क्रोध से थरथरा उठे।

गवाहों के कठघरे में जयगोपाल खड़ा था।

वही जयगोपाल, जिसने क्रांति के युद्ध में कंधे से कंधा मिला कर चलने की सौगन्ध खाई थी, जो साण्डर्स-वध में भगतसिंह का प्रमुख सहयोगी और मित्र था। वही जयगोपाल इस समय गवाहों के कटघरे में खड़ा होकर अपने मित्रों के विरुद्ध गवाही देने आया था। खड़ा ही नहीं था वरन् खड़े होकर वह अपनी मूंछें ऐंठ रहा था और व्यंग्य कर रहा था।

यह स्थिति आजादी के मतवालों से बर्दाश्त नहीं हुई। क्रांतिकारियों में सबसे कम उम्र के थे प्रेमदत्त। उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपना जूता खोला और जयगोपाल को खींच मारा। हाहाकार मच गया अदालत में। मजिस्ट्रेट ने तुरन्त अभियुक्तों को हथकड़ी लगाने का हुक्म दिया। भला ऐसा हो सकता था। इस पर एकदम हंगामा मच गया और अदालत की कार्यवाही उस दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरे दिन अभियुक्तों ने अदालत में आने से ही इनकार कर दिया। पुलिस उन्हें जबर्रस्ती अदालत में लाने के लिए एकदम खूंखार पशु की तरह टूट पड़ी। उसकी इच्छा थी कि अभियुक्तों को जबर्दस्ती लारी में लाद ले, लेकिन वे लोग ऐसी मिट्टी के नहीं बने थे, जो इस तरह के बल प्रयोग के सामने झुक जाते। पूरी कशमकश और बल प्रयोग के बाद पुलिस केवल पांच अभियुक्तों को लारी में लादने में सफल हो पाई, लेकिन जब लारी बोस्टर्ल जेल पहुंची तो पांचों व्यक्ति इस तरह आपस में चिपट गये कि पुलिस उन्हें किसी भी तरह नीचे उतारने में सफल न हो पाई। अदालत की कार्यवाही उस दिन भी न हो सकी।

दूसरे दिन पुलिस अफसरों ने दावा किया कि अदालत पहुंचकर हथकड़ी खोल दी जाएंगी। अदालत पहुंचकर पुलिस अपने वादे से फिर गई और उसने हथकड़ी न खोली। लंच के समय भगतसिंह ने हंसकर कहा- ''यारों, खाना तो खा लेने दो।'' हथकड़ियां खोल दी गई, पर लंच के बाद अभियुक्तों ने हथकड़ियां लगाने से इनकार कर दिया। उसके बाद भारतीय अदालतों के इतिहास में ऐसा दृश्य प्रस्तुत हुआ कि सारी इंसानियत त्राहि-त्राहि कर उठी। मजिस्ट्रेट बैठा रहा और उसकी आज्ञा पर पुलिस के सिपाहियों ने क्रूरतम पिटाई की। आठ पठान भगतसिंह पर लिपट गये, लेकिन इतने से भी संतोष न हुआ। पुलिस और पठान लेज उन्हें लेकर पहुंचे और वहां भी वे पीटे गये। वहां भी मुख्य निशाना भगतसिंह था। पुलिस ने भरपुर बल प्रयोग किया।

सरकार के इस घृणित कर्म के विरुद्ध देश-विदेश में नफरत की आग फैल गई। समाचार-पत्रों ने सुर्खियां देकर इस समाचार को छापा। देश-विदेश में प्रदर्शन हुए। अन्त में सरकार झुकी और एक लम्बे अवरोध के बाद फिर मुकदमा चला। इसके बीच सर्वश्री सुभाष चन्द्र बोस, बाबा गुरुदत्तसिंह, के.एल. नरीयन, राजा कलाकार, रफी अहमद किदवई, मोहनलाल सक्सेना अदालत में आये। सरकार ने अभियुक्तों को फंसाने के लिये मुकदमा चलाया था और खुद इस चक्रव्यूह में फंस गई।

तभी भगतसिंह ने एक और तुरुप चाल चल दी। जेल-सुधार-कमेटी ने जेलों में व्यवहार के संबंध में जो सिफारिशें की थीं, उन्हें लागू करने के लिए पहले सरकार ने नवम्बर, 1929 का समय घोषित किया था। फिर इसे दिसम्बर के लिए स्थगित किया, लेकिन जनवरी, 1930 बीत जाने पर भी कोई कार्यवाही न हुई। इस पर भगतसिंह ने 4 फरवरी, 1930 को एक सप्ताह का नोटिस देने के बाद फिर हड़ताल शुरू कर दी। सरकार ने घबराकर एक पत्र में प्रकाशित करके नया आश्वासन दिया। भगतसिंह ने भूख-हड़ताल तोड़ दी। इसके बाद भी उन्हें कुछ शिकायतें थीं। भगतसिंह ने फिर अदालत जाना बंद कर दिया। इस पर 'सिविल मिलेट्री गजट' नामक पत्र में एक वक्तव्य छपा कि अभियुक्तों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया। इस पर 11 फरवरी, 1930 को भगतसिंह ने एक पत्र में अपनी और बी.के. दत्त की ओर से मजिस्ट्रेट को लिखा-

''दूसरे साथी अभियुक्त हिन्दुस्तान के भिन्न-भिन्न और दूर-दूर के प्रांतों के रहने वाले हैं, इसलिए उनको अपने बंधुओं से मुलाकात की सुविधाएं मिलनी चाहिए। श्री बटुकेश्वर दत्त और कमलनाथ तिवारी ने कुमारी लज्जावती से मुलाकात की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन उनको इस आधार पर मुलाकात करने की सुविधा नहीं दी गई कि वे न तो इन दोनों की रिश्तेदार हैं और न वकील ही। बाद में इन लोगों का मुख्तारनामा प्राप्त कर लेने पर भी उन्हें मुलाकात की स्वीकृति न दी गई। इससे साफ प्रकट है कि अभियुक्तों को अपनी सफाई देने के लिए पूरी सुविधायें नहीं दी जा रही हैं। साथ ही क्रांति कुमार, जो हमारी डिफेंस कमेटी के लिये बहुत उपयोगी काम कर रहे थे, उनको एक झूठा मुकदमा (चटनी में रखकर पिस्तौल की गोली लाने का) बनाकर जेल में डाल दिया गया है। यही नहीं, जब झूठा मुकदमा उनके विरुद्ध न हो सका तो गुरुदासपुर में उनके विरुद्ध 124-ए में एक नया मुकदमा खड़ा कर दिया है।

मैं स्वयं पूरे समय के लिये वकील नहीं रख सकता, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे आदमी अदालत में रहे, लेकिन बिना कोई कारण बताए उन्हें स्वीकृति न देकर लाला अमरदास को एडवोकेट की जगह दे दी गई है। इंसाफ के नाम पर खेले जाने वाले इस नाटक को हम हर्गिज पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे हमें अपनी सफाई पेश करने के लिए कोई सुविधा या लाभ नहीं पहुंचता।

एक और बड़ी शिकायत अखबार न मिलने की है। हवालाती (अंडर ट्राइल) कैदियों से दण्ड-प्राप्त कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इनको रोजाना कम से कम एक अखबार जरूर मिलना चाहिए। अंग्रेजी न जानने वालों के लिए भी हम एक दैनिक चाहते हैं। इसलिए विरोध के तौर पर हम 'ट्रिब्यून' भी वापस कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से हमने 29 जनवरी, 1930 को अदालत में न जाने की घोषणा कर दी थी। इन असुविधाओं के दूर होते ही हमें अदालत में आने में कोई आपत्ति न होगी।''

पंजाबी किसान अब विदेश में लिख रहे हैं हरित क्रांति की नई पटकथा

-: वीना सुखीजा :-

ऑस्ट्रेलिया में आज उद्यमिता का नया पर्याय बन गए हैं हिन्दुस्तान के पंजाबी किसान। अखबार उन पर फीचर छाप रहे हैं, रेडियो उनकी कहानी सुना रहे हैं और टीवी प्रोग्राम उनकी सक्सेज स्टोरी दिखा रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों न, आखिरकार पंजाबी किसानों ने धरती के इस निचले भू-भाग में अपनी मेहनत और जज्बे से हरित क्रांति की एक नई पटकथा जो लिखी है। जी हां! मेहनत के लिए जाने, जाने वाले पंजाबी किसान पंजाब में अपने छोटे-छोटे खेतों को बेचकर ऑस्ट्रेलिया में लैंड लॉर्ड जो बन गए हैं। वैसे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों कहें? न्यूजीलैंड, लैटिन अमरीका, कनाडा और स्कैंडीनेवियन देशों में भी इन्होंने यह चमत्कार कर दिखाया है लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चमकदार तस्वीर आज अगर ऑस्ट्रेलिया में दिखती है तो इसकी वजह यह है कि आज ये पंजाबी किसानों ने न केवल अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को अनाज उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में ला खड़ा किया है बल्कि अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने खेती को भविष्य के चमकदार रोजगार क्षेत्र में शामिल कर दिया है।

आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी किसानों के खेतों में पंजाब की तरह छोटे-मोटे ट्रेक्टर नहीं बल्कि सैटेलाइट की मदद से चलने वाली मशीनें काम करती हैं। यहां इनके खेतों में कीटनाशकों का छिड़काव भारत की तरह कोई मजदूर अपने हाथ से या हाथ से चलने वाली मशीनों से नहीं करता बल्कि कम ऊंचाई पर उड़ने वाले छोटे हवाई जहाजों व हेलीकॉप्टरों के माध्यमों से होता है। कम शब्दों में कहें तो पंजाबी किसानों ने आज ऑस्ट्रेलिया में अपनी मेहनत से हरित क्रांति की नई पटकथा लिख दी है। सवाल है यह सब कैसे हुआ? दरअसल करीब सात-आठ साल पहले ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अपने यहां पूरी दुनिया से ऐसे किसानों को आमंत्रित किया था, जो ऑस्ट्रेलिया में जमीन खरीदकर खेती कर सकें।

जाहिर है इस पहल पर हिन्दुस्तान का पंजाबी किसान ही आकर्षित हो सकता था क्योंकि वह अपनी मेहनत से हिन्दुस्तान में पहले ही ऐसे कई चमत्कार कर चुका था। आज मध्य प्रदेश के शिवपुरी और खरगौर सहित कई जिलों व गुजरात के कच्छ जैसे इलाके में जो लहलहाती हुई खेती दिख रही है, वह यहां के स्थानीय किसानों की बदौलत नहीं बल्कि पंजाबी किसानों की देन है। इन इलाकों में उन्हीं की बदौलत यह चमत्कार हुआ है। महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और गोवा में भी कहीं-कहीं उनका यह कृषि चमत्कार दिखता है। ऐसे में निःसंदेह एक न एक दिन विदेशों में भी उन्हें ही यह चमत्कार करके दिखाना था।

इसलिए आज से करीब 7-8 साल पहले जब पंजाब के किसानों ने ऑस्ट्रेलिया सरकार की इस योजना के बारे में सुना तो वे पंजाब में अपने थोड़े बहुत खेतों को बेचकर ऑस्ट्रेलिया रवाना होने शुरू हो गए। ऐसा करने वाले पहले किसान थे चंडीगढ़ निवासी पुनीत भल्ला। पुनीत भल्ला के पास शहर के बिल्कुल नजदीक एक प्लाट था जो उन दिनों 2.5 करोड़ रुपए में बिका था। यही नहीं उन्होंने गांव की अपनी दो एकड़ जमीन भी बेच दी थी। यह सब बेचकर भल्ला परिवार ऑस्ट्रेलिया रवाना हुआ। वहां इस परिवार ने ऑस्ट्रेलिया के किंगलेक इलाके में इतने पैसों से करीब 400 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड खरीदकर खेती करनी शुरू कर दी।

कहां महज कुछ एकड़ और कहां 400 एकड़, दूर-दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं था। फिर अपनी मेहनत से भल्ला परिवार ने इस जमीन को सोना उगलने वाली बना दिया। उनकी कितनी कमाई हुई होगी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ ही सालों में भल्ला परिवार ऑस्ट्रेलिया में 1200 एकड़ कृषियोग्य जमीन का मालिक बन गया है। बहरहाल, भल्ला परिवार के ऑस्ट्रेलिया जाने से लेकर अब तक पंजाब और हरियाणा से तकरीबन 14 हजार किसान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं और यहां एग्रीकल्चर लैंड खरीदकर बड़ी जोत वाले किसानों में अपना नाम लिखवा चुके हैं। आज कितनी बड़ी तादाद में पंजाबी किसान ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साउथ ऑस्ट्रेलिया में भारतीय किसानों की सिंह डॉट नाम से अपनी कम्युनिटी बन चुकी है, जिसके हजारों सदस्य हैं।

दरअसल, ऑस्ट्रेलियन सरकार अपने आंतरिक इलाके की कृषि जमीन को विदेशी किसानों को बेच रही है। इस तरह की जमीन को खेती के लिए पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया गया लेकिन यह जमीन है बेहद उपजाऊ। पुनीत भल्ला व अन्य किसानों ने वहां पर महज 35 हजार रुपये प्रति एकड़ की दर से भूमि खरीदनी शुरू की थी, हालांकि अब इन पंजाबी किसानों की वजह से ही यह जमीन काफी महंगी हो गयी है लेकिन हिन्दुस्तान के मुकाबले तो बहुत ही सस्ती है। भारत के किसी भी इलाके में एग्रीकल्चर लैंड की बात करें तो बंजर भूमि भी एक एकड़ कम से कम 10 लाख रुपए में मिलेगी। लेकिन अब भी ऑस्ट्रेलिया के क्वींस लैंड

जैसे इलाके में खेती के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से कृषि योग्य जमीन बिक रही है।

भारतीय किसानों के लिए ऑस्ट्रेलिया में खेती करना अन्य देशों से काफी अलग है, क्योंकि यहां आप जमीन खरीद भी सकते हैं। जबकि कॉन्ट्रेक्ट पर खेती तो कनाडा, मोजांबिक आदि देशों में भी की जा रही है, लेकिन वहां आप अपना कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। मगर ऑस्ट्रेलिया में इसकी इजाजत है। यहां आप अपनी जमीन पर किसी भी प्रकार का टेंपरेरी या परमानेंट कंस्ट्रक्शन करके रह सकते हैं। बाकी देशों में आप उन देशों की सरकारों की शर्तों पर ही खेती करेंगे लेकिन यहां आप कभी भी जमीन अपने दामों पर बेच सकते हैं। मोजांबिक और कनाडा से इन्हीं सबकी वजह से पिछले सालों में हजारों किसान कॉन्ट्रैक्टो फार्मिंग छोड़कर ऑस्ट्रेलिया गए हैं।

तीन मुद्दों ने तोड़ी भारतीय समाज की जड़ता, आ रहा है बदलाव

-**मधु कांकरिया**, कथाकार और उपन्यासकार

पिछले साल आधी आबादी की तरफ से तीन गोले दागे गए। मी टू। तीन तलाक। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश। भारत हो या अमेरिका दोनों ही जगह मी टू का खास असर नहीं दिखा। दोनों ही जगह सत्ता के शीर्ष पुरुष अपने महिला विरोधी और मर्दवादी मानसिकता को जब-तब उजागर करते रहे। हमारे देश में सिर्फ एक बंदे एमजे अकबर को जरूर मी टू के चलते अपने सिंहासन से नीचे उतरना पड़ा।

सवाल यह है कि क्यों यह आंदोलन सिर्फ एलिट क्लास का अभियान मान लिया गया? यही नहीं बहुत से संस्थानों ने यह तक निर्णय लिया कि वे अपनी नई नियुक्तियों में महिलाओं को जगह नहीं देंगे। जो समाज दुष्कर्म जैसी घटनाओं के लिए भी महिलाओं को ही जिम्मेदार मान उन्हें नसीहत देता हो कि वे शाम आठ बजे के बाद घर से बाहर न निकलें और छोटे कपड़ें न पहने, उस समाज से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते।

अब बात सबरीमाला मंदिर की। हमने कानूनी लड़ाई जीत ली। लेकिन हुआ क्या? क्या महिलाएं बिना पुलिस के संरक्षण के अंदर घुस पाई? खुद कई महिलाएं ही महिला के प्रवेश के विरुद्ध खड़ी हो गई। हमें इस मनोवृति को समझाना होगा। क्या कारण था कि महिला को ही महिला के प्रवेश से आपत्ति हो गई?

इसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि सदियों से दिमाग में घुसे धर्म और ईश्वर के डर ने महिला की स्वतंत्र सोच को पनपने ही नहीं दिया। वे उसी प्रकार सोचने लगीं जैसा पैतृक समाज चाहता था। सिर्फ सबरीमाला मंदिर ही क्यों भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जहां महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। यदि स्त्री होने का मतलब सृजन, प्रेम और सम्पूर्णता है तो स्त्री कभी भी कैसे अपवित्र हो सकती है?

ज्यादातर मस्जिदों में औरतों का जाना मना है। यहूदियों के सिनेगॉग में स्त्रियों को पुरुषों से अलग उनकी नजरों की आड़ में बिठाया जाता है। कहने का आशय यह है कि संसार का कोई भी धर्म स्त्री को पुरुष के बराबर नहीं मानता है। क्या सिर्फ देह ही स्त्री का सामाजिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक सत्य है? इसलिए स्त्री समानता की लड़ाई के लिए जरूरी है कि समस्या की जड़ों यानी सामंती और मर्दवादी मानसिकता पर ही प्रहार किया जाए।

इस मर्दवादी मानसिकता को खुराक मिलती है हमारे धार्मिक मान्यताओं से, रीति-रिवाजों से, मनु स्मृतियों से। यदि हम स्त्री को सम्पूर्णता देना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें एक ऐसे समाज की संरचना करनी होगी जो उच्च मूल्यों को ग्रहण कर सके। तो जरूरी है समाज को धर्मसत्ता की जकड़न से मुक्त करने की और धर्म की परिभाषा बदलने की। मंदिरों में प्रवेश की लड़ाई लड़ने की बजाय अच्छा हो हम स्त्री विरोधी धर्म और मंदिर के मोह से ही ऊपर उठें। बहरहाल, इन दिन मुद्दों ने जड़ता तोड़ी है। विरोध तो हुआ है पर इन तीन मुद्दों ने बदलाव की राह भी खोली है, जो आने वाले दिनों में दिखाई देगा।

संदर्भ : परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देशों के बीच टकराव बढ़ने के खतरे और युद्ध का उन्माद

राष्ट्रीय सुरक्षा पर सावधानी भरा रवैया जरूरी

-: राजदीप सरदेसाई :-

युद्ध कोई क्रिकेट मैच नहीं है और हवाई हमले को राजनीतिक तमाशे में नहीं बदलना चाहिए। लेकिन, हम चुनाव के मौसम में हैं और पाक स्थित आतंकी शिविरों पर किए 'गैर-सैन्य' हमले के बाद जश्न इसकी पुष्टि करता है। चूंकि ऐसा लगता है कि राष्ट्र का सामूहिक अवचेतन पुलवामा में 40 सीआरपीएफ सैनिकों की क्रूर हत्या का बदला देने के बाद ही संतुष्ट होगा, तो सवाल उठता है कि क्या पुलवामा और पाकिस्तान ही 2019 के आम चुनाव को प्रभावित करेंगे?

पुलवामा के पहले वाले हफ्ते में जहां भाजपा नेतृत्व 'मजबूत सरकार' बनाम 'महामिलावट गठबंधन' की बात कर रहा था वहीं, विपक्ष रोजगार से लेकर खेती के संकट तक मोदी सरकार के नाकाम वादों पर केंद्रित था। लेकिन, पुलवामा और हवाई हमले के बाद भाजपा के राजनीतिक प्रबंधक चुनाव को 'राष्ट्रवाद' की भावुक थीम और शत्रु को सबक सिखाने की राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाने वाले नेता के रूप में मोदी की 'स्ट्रांगमैन' छवि पर केंद्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। संदेश यही है कि भाजपा के खिलाफ वोट सिर्फ मोदी के खिलाफ वोट नहीं है बल्कि यह राष्ट्र विरोधी ताकतों के पक्ष में वोट है।

'आइए, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ दें' वाला कट्टर राष्ट्रवादी टेलीविजन मीडिया और सोशल मीडिया पर चीअरलीडर्स की विशाल सेना के होते ऐसा माहौल बनाने की मुहिम छेड़ दी गई है, जिसमें सरकार पर सवाल उठाने वाले पर राष्ट्र विरोधी होने का ठप्पा लगा दिया जाए। पुलवामा में खुफिया नाकामी अथवा दिशाहीन कश्मीर नीति हो, सरकार ने एकजुट राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के बहाने अपनी नाकामिया छिपानी चाही है। उन्मादपूर्ण प्रतिक्रिया इस बेतुकी हद तक पहुंच गई है कि सुनील गावस्कर और सचिन तेंडुलकर जैसी क्रिकेट की किंवदंतियों की देशभक्ति पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि वे विश्व कप में पाकिस्तान के बहिष्कार का समर्थन नहीं करते। पहली बार नहीं है कि भाजपा ने पार्टी और इसके नेतृत्व को 'हिन्दू राष्ट्रवाद' के समकक्ष रखने का प्रयास किया है। 1990 के दशक में जब भाजपा बाबरी मस्जिद ध्वंस की पृष्ठभूमि में पहली बार राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी थी, तो हिन्दू एकजुटता का खुला सांप्रदायिक एजेंडा 'राष्ट्रवादी तेवर' के साथ मौजूद था। इसने बांग्लादेश युद्ध के हमारे नायकों में से एक रहे जनरल जेएफआर जेकब सहित कई रिटायर्ड फौजी जनरलों को आकर्षित किया था। नैतिक रूप से समझौता करने वाली कांग्रेस किया था। नैतिक रूप से समझौता करने वाली कांग्रेस पार्टी के मातहत दंगों व हत्याओं से जख्मी 1980 के दशक के बाद भाजपा को ऐसी पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया गया जो भारत को मजबूत सरकार व दृढ़ नेतृत्व प्रदान करेगी और विभाजनकारी 'छद्म धर्मनिरपेक्ष' ताकतों के आगे नहीं झुकेगी।

यही तब किया गया जब मोदी ने भाजपा का विवादास्पद 2002 का गुजरात अभियान शुरू किया। कारसेवकों से भरे ट्रेन के डिब्बे में आग लगाने वालों की पहचान न सिर्फ स्थानीय मुस्लिमों बल्कि पाकिस्तान से जोड़ने से गुजराती 'अस्मिता' के नाम पर राष्ट्रवादी जुनून जगाया गया। विहिप के नेतृत्व में संघ परिवार ने चतुराई से इस धार्मिक-राष्ट्रवादी आवेश को भुनाकर भाजपा के लिए चुनाव में दो-तिहाई बहुमत की जीत सुनिश्चित की।

क्या 2002 का यही 'गुजरात मॉडल' अब 2019 में राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने की मंशा है? साबरमती एक्सप्रेस के कंपार्टमेंट को जलाने वाले गोधरा के मुस्लिमों की जगह पुलवामा के आत्मघाती हमलावर मुस्लिम और हमारे सुरक्षा बलों पर पथराव करने वालों को रखिए। फिर जैश-ए-मोहम्मद जैसे जेहादी गुट और पाक फौज के उनके संरक्षकों को रखें, तो फिर भीतरी-बाहर शत्रुओं से 'राष्ट्र खतरे' में होने का डरावना दृश्य तैयार किया जा सकता है। ऐसी ही कोशिश तब की गई जब अमित शाह ने असम के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील लखीमपुर जिले में एक राजनीतिक रैली में चेतावनी देते हुए कहा कि राज्य को एक और कश्मीर नहीं बनने दिया जाएगा। या जब मेघालय के राज्यपाल तथागत राय ने कश्मीरियों के बहिष्कार का शर्मनाक समर्थन किया।

सवाल है कि यह विषैला संदेश वोटर के व्यवहार को कितना प्रभावित करेगा? अब तक कश्मीर या पाकिस्तान कभी किसी आम चुनाव का केन्द्रीय मुद्दा नहीं रहा, 1999 के चुनाव में भी नहीं, जिसमें वाजपेयी के नेतृत्व वाली भाजपा ने कारगिल विजय के बाद जीत हासिल की थी। 'युद्ध जैसा' वातावरण राष्ट्र को जरूर एकजुट करता है लेकिन, क्या यह इतने विराट व विविध देश में सभी मतदाताओं के लिए एकमात्र मुद्दा होगा, यह निश्चित नहीं है। उत्तरी भारत में बंटवारे के जख्म अब भी मौजूद हैं और गहरा सांप्रदायिक विभाजन है, वहां पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई से राजनीतिक एकजुटता होने और इससे सत्तारूढ़ दल तथा मोदी के मर्दाना नेतृत्व को निर्णायक बढ़ावा मिलने की संभावना है। हालांकि परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसियों के बीच टकराव को बढ़ाने के खतरे असली हैं और 'उरी' जैसी फिल्म सिनेमा हॉल में चाहे जितना 'जोश' जगाए पर जमीनी वास्तविकताएं अधिक सतर्कता बरतने की मांग करती है। कोई राजनीतिक दल या नेता चाहे जितना ही दृढ़ प्रतिज्ञ हो, शहीदों के पार्थिव शरीरों के घर लौटने की स्थिति से आसानी से नहीं निपट सकता है।

1971 के बाद पहली बार नियंत्रण रेखा पार करके पारा ऊंचा उठाने के बाद मोदी सरकार अब 'शत्रु' के साथ शांति की राह पर आसानी से नहीं चल सकती। न ही भावनात्मक रूप से उत्तेजित इसके कार्यकर्ता एक ही सर्जिकल स्ट्राइक से संतुष्ट होंगे। न ही किसी भारत-पाक टकराव में फंसे कश्मीरी लोगों तक समझौते का हाथ बढ़ाए बिना सीमा के आर-पार युद्ध लड़ा जा सकता है। टीवी स्टूडियो के विपरीत असली दुनिया में लंबी अवधि के रणनीतिक लक्ष्यों और अल्पावधि के चुनावी फायदे में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। न्यूज चैनल टीआरपी की ओर देख सकते हैं पर सरकार 'वॉर फॉर वोट' का रवेया नहीं अपना सकती। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उसे अधिक सावधानी भरा व समझदार रूख रखना होगा।

पुनश्च : पिछले हफ्ते चेन्नई के एक अग्रणी कॉलेज के चुनावी शो में जिन छात्रों से मैंने राय मांगी उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है और न वे पाक से खेल संबंध तोड़ने के पक्ष में थे। हां, हम सब 'देशभक्त' भारतीयों में पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को न रोकने के खिलाफ जायज गुस्सा है और हमें अपने पेशेवर सशस्त्र बलों पर गर्व है। लेकिन, आइए सरकार की प्रतिक्रिया को उन्मादी खबरों से निकलती युद्ध की गूंज से प्रभावित न होने दें।

सरोज वर्मा को सत्यार्थ भूषण की उपाधि से सम्मानित किया

उदयपुर। श्रीमद्दयानन्द सत्यार्थ प्रकाश न्यास उदयपुर द्वारा प्रकाशित सत्यार्थ सौरभ पत्रिका से विदित हुआ है कि सत्यार्थ दूत श्रीमती सरोज वर्मा को सत्यार्थ प्रकाश पहेली 2018 के पुरस्कार घोषित करने पर उनको 5100 रुपए का पुरस्कार देते हुए 'सत्यार्थ भूषण' की उपाधि से अलंकृत किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश पहेली 2018 की विजेता होने पर उन्हें हार्दिक बधाई।

परमात्मा निराकार है सर्वव्यापक है

सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास में प्रकाश किया है

प्रश्न : ईश्वर साकार है वा निराकार ?

उत्तर : **निराकार। क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता। जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते। क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण, क्षुधा, त्रषा और रोग, दोष, छेदन, भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है।**

मनुष्य जैसा स्वयं है वह वैसा ही ईश्वर का स्वरूप देखना चाहता है। यह वही व्यक्ति है जो वैदिक ज्ञान से दूर है। इस अज्ञानता के कारण ही वह अनेक देवी देवताओं की मूर्ति बना उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर पूजन में रुचि रखते हैं। चौबीस अवतार मान लिए। मूर्ति पूजा एक व्यावसायिक कुचक्र है जिसमें मनुष्य को भ्रमित कर धर्म के ठेकेदारों ने भोले लोगों को बांधा हुआ है। सत्य यह है कि वह न तो अवतार के रूप में आता, न ही जन्म लेता न मरता न दु:ख सागर में आकर दु:ख भोगता। परमात्मा शरीर धारण नहीं करता। सर्वशक्तिमान है वह अपने कार्य अर्थात् उत्पत्ति पालन प्रलय कर्मफल देना सब अपनी सामर्थ्य अथवा बिना किसी अन्य की सहायता के ही करता है।

यजुर्वेद के अध्याय 32 के मं. 3 में दिया है

'न तष्य प्रतिमाऽस्ति'

अर्थात् उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं और निराकार क्यों है उस पर यदि आकार वाला ही होता तो क्या होता इस विषय पर विचार करते हैं।

— यदि आकार वाला होता तो उसके आगे पीछे चापलूसों की भीड़ होती उनमें भी वह व्यक्ति होते जो धनाढ्य होते, बलवान होते, अस्त्र-शस्त्र वाले होते निर्बल, विद्वान, न्यायशील, पक्षपात न करने वाले, सत्यवादी तो वहाँ पहुँच ही न पाते।

— आकार वाला होता तो कहीं न कहीं किसी न किसी परिवार में जन्मता तब लोग उसकी जाति बिरादरी स्थान, पूरब-पश्चिम, भारत या यूरोप, अमरीका का कहां का है, निकाल लेते फिर उसकी जाति वाले उसे अधिक चाहते इससे वह एक स्थानीय व जाति का होकर रह जाता। जातिवाद का दोष लगता जो उचित नहीं।

— आकार वाला होता तो भोजन भी करता लोग उसको बढ़िया स्वादिष्ट वस्तुएं खाने को देते, वस्त्र भी देते, वह वातानुकूलित घर में भी रहता। अधिक से अधिक धन रखने का प्रयत्न भी करता और बहुत से व्यक्ति अपना कार्य कराते उसके लिए उसे स्वर्ण आदि भी देते क्योंकि उनके बुरे कार्यों को भी करता और जो सज्जन हैं न कुछ दे पाते न कुछ उनका कार्य हो पाता।

— आकार वाला होता तो लोभ, मोह, ईर्ष्या में भी फंसा रहता संतान, भाई-बहन भी होते, माता-पिता होते। पहले तो उनके लिए ही करता बाद में अन्य का कार्य करता।

— आकार वाला होता तो उसकी कहीं न कहीं लड़ाई भी हुआ करती हार-जीत भी होती। फिर सर्वशक्तिमान कैसे होता।

— यदि हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या अन्य होता तो जिस सम्प्रदाय में होता वह उसको अपने सम्प्रदाय वाला मान अन्य से लड़ाई-झगड़ा करवाया करते। साम्प्रदायिक होने का दोष लगता।

— हिन्दुओं में ही होता यदि ब्राह्मण जाति में होता तो ब्राह्मण किसी को कुछ न समझते। ईश्वर को अपनी जाति का होने से अभिमान में चूर रहते। क्षत्रिय या वैश्यों में या शूद्रों में होता तो उनमें भी जातिवाद व प्रमाद का प्रभाव होता।

— जिस परिवार में होता पुत्र पौत्र भी होते, पौत्र के भी पौत्र होते तो वह उसे वस्त्र, भोजन आदि देने में दुखी होते। सोचते कि काम दुनियां का करता है और खाता हमारे यहां है। उसे अपने ऊपर बोझ समझते, बीमार हो जाता तो इलाज भी न कराते।

— राजनीति में होता तो राजनीतिज्ञ उसकी प्रतिदिन कमियां गिनाने में रहते, दोषारोपण करते रहते, उसे शांति से रहने नहीं देते।

— पौराणिक उसे ऐसे जोड़ देते जैसे कृष्ण को दधि चुराने वाला, माखन चोर, गोपियों की मटकी फोड़ने वाला, कुब्जा के साथ संसर्ग करने वाला, नग्न स्नान करती कन्याओं के वस्त्र हरण कर निहारने वाला बना देते।

— आकार वाला होता तो दुनियां अर्थात् जो यह ब्रह्माण्ड, सूर्य, तारे, चन्द्रमा जैसा सौरमण्डल है और सभी नियम में हैं जैसा कि सूर्योदय-सूर्यास्त निश्चित समय पर होते रहते हैं। आकाशिय पिण्ड निश्चित कक्षा में गति करते रहते हैं। पुण्य, फल, व्रक्ष, नदी, पर्वत सबका अपना-अपना बनना व परिवर्तन है वह कैसे होता। मनुष्यों को कर्मफल कैसे मिलता क्योंकि सर्वत्र तो वह देख नहीं सकता था आ जा नहीं सकता था। एक स्थान पर ही रह सकता था। सर्वव्यापक व सर्वान्तर्यामी भी न रहता एक देशीय होता।

— मनुष्य जैसा आकार वाला होता तो वैसी ही बुद्धि होती उतना ही सोचता, विचार करता जितना मनुष्य करता है अर्थात् अल्पज्ञानी होता। पूर्ण ज्ञानी न होता सीमित स्थान व आकार वाला होने से सीमित ही कार्य कर पाता। सबको कैसे जान पाता, सबके मन की कैसे जान पाता। अत: एक रजिस्टर मुनीम व अन्य कार्यकर्ता कम्प्यूटर नेटवर्क भी चलाता फिर भी वह पूरा कार्य संचालन व जानकारी एक साथ नहीं कर पाता।

— आकार वाला होता तो सृष्टि कितनी बड़ी है, कहां तक है। अल्पबुद्धि मानव कल्पना भी नहीं कर सकता। आकार वाला होकर पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकता, अल्पज्ञ होता।

यहां विषय यह है कि जो लोग लोभ व अज्ञानता से ईश्वर को आकार वाला, एक देशीय, मूर्ति मान कर मंदिरों में खड़े रहने वाला, अवतार, गुरु को ईश्वर सदृश, गुरु को ईश्वर से बड़ा, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि में स्थित मानते हैं। यह समाज की उन्नति के विरुद्ध एक अंधविश्वास व भ्रम है। व्यवसायियों धर्म के ठेकेदारों ने तो मूर्ति पूजा को व्यवसाय हेतु चला रखा है। इसलिए जनता को भ्रमित कर मूर्ति पूजा, गुरुऽमवाद, तीर्थयात्रा आदि में फंसाया हुआ है यही कारण है कि समाज में चारों ओर चिंता, बेचैनी, अनिश्चितता, भ्रम, ईर्ष्या-द्वेष, लड़ाई-झगड़े, अपराध, अनाचार बढ़ कर दु:ख ही दु:ख बढ़ रहा है।

यदि हम अब भी वेदों को जानने लगें, मानने लगें तो ईश्वर को लेकर जो सांसारिक बखेड़ा, उपद्रव, साम्प्रदायिकता बढ़ रही है, वह समाप्त हो जायेगी। ईश्वर जैसा कि सच्चिदानन्द स्वरूप निराकार, न्यायकारी, दयालु, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वान्तर्यामी अजर,अमर, अनादि सृष्टिकर्त्ता आदि वैदिक स्वरूप वाला है यही मानना योग्य है।

आज जो ईश्वर को अनेकेश्वरवाद, बहुदेवतावाद जेसा माना जा रहा है। वह भ्रांतिपूर्ण अंधविश्वास है। ईश्वर क्या है, क्या करता है, उसे जानने हेतु ऋषि दयानन्द के मन्तव्य को जानना होगा, वेदों की ओर लौटना होगा।

- डॉ. बिजेन्द्रपाल सिंह
मो.: 8979794715

स्वर्ण जयंती समारोह .....

(पृष्ठ 2 का शेष)

इसी प्रकार के अनेक मुद्दे हैं जिसमें जनशक्ति और धनशक्ति की भी जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए समान शिक्षा पद्धति का मुद्दा लिया जा सकता है। अमीर परिवारों के लिए केन्द्रीय विद्यालय, जहां सीबीएसई का कोर्स है। जिस कोर्स के माध्यम से केन्द्रीय विद्यालय के विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं और उच्च पदों पर पहुंचते हैं परंतु प्रांतीय सरकारें अपना पाठ्यक्रम स्वयं तैयार करती हैं और पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशन से करोड़ों रुपए की कमाई करती हैं। गरीब परिवारों के करोड़ों छात्र-छात्राओं का भविष्य अंधकारमय करते हैं। यदि सार्वदेशिक सभा के चार-पांच नेता प्रांत के मुख्यमंत्री से मिलकर समान शिक्षा पद्धति के लिए आग्रह करें तो लाखों-करोड़ों परिवार आर्य समाज के प्रशंसक बन सकते हैं।

समारोह में निम्नलिखित घोषित कार्यक्रम से आर्य जगत में आशा का संचार हुआ है-

(1) आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द जी की दूसरी जन्मशती के अवसर पर वर्ष 2025 तक एक लाख आर्य युवक एवं युवतियों को आर्य समाज में दीक्षित करना। (2) 200 जीवनदानी समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना। (3) 200 वानप्रस्थ एवं संन्यासी तैयार करना। (4) एक हजार अल्पकालिक एवं पूर्णकालिक युवा निर्माण शिविर आयोजित करना। (5) इण्टरनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अधिक से अधिक लोगों तक वैदिक विचारधारा को प्रचारित एवं प्रसारित करना।

इस समारोह में सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद हरियाणा के प्रधान ब्रह्मचारी दीक्षेन्द्र जी द्वारा तैयार की गई स्वामी इन्द्रवेश जी के जीवन पर डॉक्यूमेन्ट्री फिल्म अत्यन्त आकर्षक एवं प्रभावशाली रही जिसे लोगों ने विशेष रूप से पसन्द किया तथा इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। बेटी बचाओ अभियान की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संयोजक बहन पूनम आर्या, बहन प्रवेश आर्या तथा ब्रह्मचारी दीक्षेन्द्र ने उपस्थित जनसमुदाय को धन्यवाद दिया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में स्वामी आर्यवेश जी ने समस्त महानुभावों द्वारा किये गये सहयोग के लिये साधुवाद एवं धन्यवाद ज्ञापित किया।

चीन के आर्थिक हितों पर प्रहार जरूरी

-: डॉ. श्रीनाथ सहाय :-

चीन ने मसूद अजहद को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के प्रस्ताव को संरासंघ की सुरक्षा परिषद ने वीटो कर दिया। यह कोई अप्रत्याशित नहीं था, सामरिक व आर्थिक हितों के नजरिए से चीन को पाक की जरूरत है। उसने चौथी बार जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने के प्रस्ताव को वीटों किया। जैसे चीन ने मामले को अंतिम समय तक लटकाए रखा और जिस तरह तकनीकी आधार बताकर प्रस्ताव को रोका, वह चीन की नीयत को दर्शाता है। घटनाक्रम के कई निष्कर्ष हमारे सामने हैं। ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने इस तरह की हरकत से भारत को चिढ़ाया हो। पाकिस्तान के साथ हाल ही में उत्पन्न तनाव के बाद चीन ने जिस तरह से सहयोगात्मक रूख अपनाते हुए पाकिस्तान को इकतरफा समर्थन देने से परहेज किया। उससे ऐसा लगने लगा था कि वह भारत के साथ खड़ा होने को तैयार है किंतु अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों द्वारा सुरक्षा परिषद में अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किए जाने के लिए लाए गए प्रस्ताव को चीन ने ये कहकर रोक दिया कि बिना पर्याप्त सबूतों के ऐसा करना उचित नहीं होगा हालांकि उसके ऐसा करने से भारत को आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान के साथ चीन के केवल कूटनीतिक रिश्ते ही नहीं हैं।

पुलवाला में आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से की गई एयर स्ट्राइक से पूरे देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। ऐसे में चीन द्वारा पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना मसूद अजहर का बचाव करने के चलते पाकिस्तान के साथ चीन के प्रति गुस्सा चरम पर है। वहां से ये अभियान उभर कर आया कि हमें चीन समेत उन सब देशों को सबक सिखाना चाहिए जो भारत के हित के खिलाफ नजर आते हों। चीन भारत का सबसे बड़ा कारोबार सहयोगी है। भारत में आयात किए जाने वाले सामान में गिफ्ट आइटम्स, टीवी, कम्प्यूटर के सामान, फोन और लैंप्स वगैरह शामिल हैं।

देश में चीनी वस्तुओं का कारोबार इतना व्यापक है कि बीते साल दीवाली के त्योहार से पहले वाले कुछ हफ्ते में ही केवल दिल्ली में 1000 करोड़ के उत्पाद बिक चुके थे। इस समय होली का त्योहार सामने है। भारतीय बाजार चीनी उत्पादों से पटे पड़े हैं। भारत को डब्ल्यूटीओ का सदस्य होने के नाते चीनी वस्तुएं आयात करना आवश्यक हो जाता है। चीन और भारत का व्यापारिक साझेदारी 4.6 लाख करोड़ का है और चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस कारण भारत को चीन से व्यापारिक साझेदारी खत्म करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। भारत में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण की प्रक्रिया कुंद सी पड़ गई है। भारत निर्यात की तुलना में 7 गुना ज्यादा माल चीन से आयात करता है। भारत इलेक्ट्रोनिक के 32.02, न्यूक्लियर रिएक्टर, बायलर्स और पार्ट्स के 17.01 प्रतिशत, आर्गनिक केमिकल्स 9.83 प्रतिशत फर्टिलाइजर्स 5.3 प्रतिशत आयात करता है। कृषि और आज के मानव का अहम हिस्सा मोबाइल जब हम चीन से आयात करने पर मजबूर हैं फिर चीन के साथ व्यापार बंद करना उचित नहीं लगता। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें विदेशी वस्तुओं के उपयोग से मुक्त होने की जरूरत है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि ऐसा तभी होगा, जब हम खुद अपनी चीजें बनाएंगे। जब मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया में भी विदेशी निवेश हो रहा है, फिर बहिष्कार की बात नाकाफी दिखती है। चीन को केवल हम उसके टिकाऊपन के खिलाफ मात दे सकते हैं। त्योहारों के सीजन में चीनी झालरों और पटाखों के इस्तेमाल न करने से केवल हम बहिष्कार की मुहिम नहीं चला सकते हैं।

भारत वर्तमान में चीन से आइरन और स्टील 5.82 प्रतिशत, प्लास्टिक और उससे बनी चीजें 2.74 प्रतिशत, फोटोग्राफी उपकरण 2.09 प्रतिशत, बोट्स 2.05 प्रतिशत, आयरन व स्टील से बनी चीजें 1.92 प्रतिशत और रेलवे के अलावा अन्य वाहनों के 1.81 प्रतिशत पुर्जे खरीदता है। भारत विगत वर्षों से सौन्दर्य प्रसाधन, रक्षा उपकरण के सामान से लेकर यात्रा-सुविधा के साधन जैसे रेल, मोटर-गाड़ी आदि के लगभग सभी पार्ट्स चीन से ही आयात करता है, फिर चीन की वस्तुओं के आयात पर बात करना बेकूफी भरी समझ में आती है। देश का बुनियादी ढांचा कृषि जब अभी चीन के यंत्रों और फर्टिलाइजर्स से होती है, तब तक चीनी सामान का बहिष्कार किस हद तक जायज कहा जा सकता है। दक्षिण एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के रास्ते में वह भारत को सबसे बड़ा रोड़ा मानता है। पाकिस्तान से खैरात में मिली जमीन पर वन बेल्ट वन रोड के उसके महत्वाकांक्षी प्रकल्प में भारत ने जिस तरह अड़ंगा लगाया उससे भी भीतर-भीतर काफी नाराज है। पुलवामा हमले के बाद के घटनाचक्र में भले ही उसने भारत के साथ सौजन्यतापूर्ण व्यवहार किया हो किन्तु उसे ये डर भी सता रहा था कि पाकिस्तान के पूरी तरह दब जाने से भारत का पलड़ा यदि भारी हो गया तब वह चीन के दूरगामी हितों के लिए नुकसानदेह होगा। पाक अधिकृत कश्मीर में भारत के संभावित हस्तक्षेप और बलूचिस्तान की आजादी की मुहिम को भारत का अप्रत्यक्ष समर्थन भी चीन की परेशानी का कारण हैं।

पहला यह कि भले ही भारत वैश्विक सहयोग के तमाम मंचों पर चीन के साथ खड़ा हो मगर चीन भारत के मुकाबले पाक को तरजीह देगा। पाक न केवल उसका सामरिक सहयोगी है बल्कि चीन के साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने वाली 'वन बेल्ट, वन रोड' जैसी महत्वाकांक्षी योजना का साझीदार भी है। पाकिस्तान में कई विद्युत व बड़ी परियोजनाएं चीन के द्वारा पूरी की जा रही हैं। इसके अलावा चीन को शिनजियांग प्रांत में उईगर चरमपंथियों से मुकाबले के लिए पाक की मदद की जरूरत होती है। चीन भविष्य के अफगानिस्तान में भी अपना महत्वपूर्ण भूमिका चाहता है और प्राकृति संसाधनों के दोहन के लिए उसे पाक की जरूरत होगी। चीन के हुक्मरान मोदी सरकार से अच्छे रिश्ते बनाकर चल रहे हैं लेकिन वे पाकिस्तान को छोड़ने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे क्योंकि चीन ने वहां बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश कर रखा है।

मौसम में बदलाव को लेकर फ्रांस में 220 शहरों में 3.5 लाख लोगों ने मार्च किया

पेरिस। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर फ्रांस सड़क पर उतर आया है। वहां 220

शहरों में 3.5 लाख से ज्यादा लोगों ने मार्च किया। राजधानी पेरिस में ही 45 हजार लोग शामिल हुए। इसे मार्च ऑफ द सेंचुरी नाम दिया गया। हाथों में गमले, जीवों के चित्र वाले बैनर-पोस्टर लिए प्रदर्शनकारियों का कहना था कि हमारा विरोध उन लोगों के खिलाफ भी है, जो खरबों रुपए कमा रहे हैं पर पर्यावरण के लिए कुछ नहीं कर रहे। मौसम में बदलाव का असर इंसानों के साथ ही धरती के सभी जीवों पर पड़ रहा है। अगर इन्हें बचाना है तो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्य को हासिल करना जरूरी है। इस समझौते के तहत धरती के तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य है। जलवायु परिवर्तन को लेकर नीदरलैंड में 11 मार्च को 40 हजार लोगों ने मार्च किया था। इसके बाद 15 मार्च को 100 देशों के छात्रों ने प्रदर्शन किया था।

जीवों की चिंता— मार्च में लोग मौसम में बदलाव से खतरे का सामना कर रहे जीवों की डमी के साथ पहुंचे।

ये संकट दुनिया के लिए मौका 13 लाख करोड़ का बाजार उभरा

ग्लोबल वार्मिंग ने दुनिया के लिए मौके भी दिए हैं। इसने कोयला, डीजल-पेट्रोल जैसे परंपरागत ईंधन के बजाय अक्षय ऊर्जा (रिन्यूएबल) के विकल्प अपनाने के लिए मजबूर किया है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक- 2020 तक सोलर पॉवर, विंड पॉवर जैसे अक्षय ऊर्जा का 13 लाख करोड़ का बाजार हो जाएगा। बिजली बचाने वाले यंत्रों, एलईडी बल्ब का बाजार सालाना 40 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है।

टेक्नोलॉजी से पेड़ बचाने की मुहिम— पेड़ों को बचाने के लिए ओडिशा में ईको क्लब स्कूल शुरू हुए हैं। बड़े पैमाने पर ई-लर्निंग प्रोग्राम चल रहे हैं। अमेरिकी संस्था द ग्रीन फ्यूचर के मुताबिक यदि 1 अरब पौधे रोपे जाते हैं, तो दुनिया में पेड़ों की संख्या 1 प्रतिशत बढ़ेगी।

30 मार्च को अर्थ ऑवर— 30 मार्च को अर्थ ऑवर होगा। इस साल की थीम बिजली बचाने के साथ धरती को हरा-भरा बनाना है।

पर्यावरण की रक्षक : 16 साल की ग्रेटा नोबल के लिए नामित की गई

इस साल के नोबेल शांति सम्मान के लिए पर्यावरण की रक्षक 16 साल की ग्रेटा थनबर्ग को नामित किया गया है। उसने पिछले साल अगस्त में क्लाइमेट चेंज के खिलाफ क्लास छोड़कर स्वीडन की संसद के बाहर प्रदर्शन किया था। उसके बाद तीन सांसद उसे नोबेल देने का प्रस्ताव लाए।

पंजीयन संख्या : RAJHIN(RNI)2000/2567
डाक पं. सं. : Jaipur City/264/2018-20

जयपुर में आयोजित विशाल गोविन्दोत्सव में सत्यव्रत सामवेदी को राजस्थान गौरव सम्मान

पूर्व राज्यपाल नवरंगलाल टिबरीवाल सामवेदी जी को शॉल ओढ़ाते हुए एवं गोपाल शर्मा माल्यार्पण करते हुए।

जयपुर, 24 मार्च। स्टेच्यू सर्किल के निकट होटल हवेली में रविवार को गोविन्दोत्सव मनाया गया। हजारों की संख्या में महिलाओं एवं पुरुषों ने डफ, चंग और ब्रज के कलाकारों संग ब्रज के फूलों की होली का जमकर लुत्फ उठाया। इस अवसर पर सत्यव्रत सामवेदी को राज्य गौरव सम्मान से नवाजा गया। यह आयोजन जयपुर महानगर टाइम्स के प्रसिद्ध सम्पादक गोपाल शर्मा द्वारा आयोजित किया गया था।

गोपाल शर्मा ने सत्यव्रत सामवेदी का परिचय देते हुए कहा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के यशस्वी एवं सर्वाधिक ओजस्वी वक्ता, स्वतंत्रता सेनानी तथा महात्मा गांधी के साथी पंडित जयदेव वेदालंकार के सुपुत्र सत्यव्रत सामवेदी का जन्म 26 दिसम्बर, 1937 में हरिद्वार में हुआ। पंडित जयदेव को स्वतंत्रता संग्राम में 26 वर्ष का कारावास हुआ। माताजी ने अध्यापिका का कार्य करके संतान का पालन पोषण किया। पंडित जी को सहारनपुर का महात्मा गांधी कहा जाता था। पंडित जी ने वारंगल (हैदराबाद) में 100 आर्य समाजों की स्थापना की और उन पर मुसलमानों द्वारा मरणान्तक आक्रमण हुए।

सामवेदी जी की प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल कांगड़ी में हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय से बी.ए. ऑनर्स और एम.ए. हिन्दी साहित्य में किया। पंजाब विश्वविद्यालय से बी.एड., राजस्थान विश्वविद्यालय से इतिहास में एम.ए. तथा विधि स्नातक किया।

सन् 1975 से स्वतंत्रता सेनानी श्री छोटू सिंह (पूर्व विधायक) के साथ आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान का कार्य किया और दो शताब्दी समारोहों के आयोजन में मुख्य भूमिका रही। अनेक बार आर्य प्रतिनिधि सभा, राजस्थान के महामंत्री और अध्यक्ष रहे। सन् 2002 में सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री एवं 2005 से सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के कार्यकारी प्रधान हैं। विद्या समिति एवं शिक्षा समिति द्वारा संचालित स्नातकोत्तर महाविद्यालयों, दो उच्च माध्यमिक विद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं विधि महाविद्यालय के अध्यक्ष हैं।

राजस्थान के गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के 1993 से अध्यक्ष एवं राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक अधिनियम 89 एवं नियम 93 तथा इसके बाद राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति शिवकुमार शर्मा की अध्यक्षता में गठित फीस कमेटी को राजस्थान उच्च न्यायालय से भंग करवाया और 1993 से गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं के लिए संघर्षरत हैं।

1960 से शराबबंदी के लिए अनेक प्रदर्शन एवं 1980 में 124 विधायकों के हस्ताक्षर कराके राजस्थान में पूर्ण शराबबंदी कराई। लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित लोक समिति के अध्यक्ष रहे। जॉर्डन एवं ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। राजस्थान में सती प्रथा के विरोध में जबरदस्त आंदोलन तथा मरणांतक हमला जिसमें बाल-बाल बचे।

भारतवर्ष की दूसरी काशी माने जाने वाले जयपुर में पौराणिक महंत, राजनेता एवं भारतीय प्रशासनिक अधिकारी वैदिक साहित्य एवं गीता तथा आर्ष ग्रंथों पर सामवेदी जी के भाषणों का आयोजन करते हैं और देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से लेकर प्रत्येक प्रांत के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्री सामवेदी जी का भाषण सुनकर महर्षि दयानन्द एवं आर्य समाज के प्रशंसक हो गए हैं।

गोपाल शर्मा ने कहा कि सत्यव्रत सामवेदी राजस्थान के गौरव हैं और इनके उपनिषदों, वेदों और गीता के मौलिक भाषणों को सुनकर लाखों राजस्थानी भाव विभोर हो जाते हैं। अत: इस अवसर पर सत्यव्रत सामवेदी को राजस्थान के गौरव के सम्मान से सम्मानित करने पर हम अत्यन्त हर्ष का अनुभव कर रहे हैं।

महर्षि दयानन्द का 195वां जन्मदिवस मनाया

जयपुर। आर्य समाज किशनपोल बाजार जयपुर ने महर्षि दयानन्द के 195वें जन्मदिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में विशिष्ट अतिथि राजस्थान लोकायुक्त एस.एस. कोठारी, प्रमुख अतिथि सत्यव्रत सामवेदी, विद्वान गण डॉ. मुरारी लाल पारीक, भजनोपदेशक केशव जी शर्मा, सुमेरपुर, ठा. विक्रम सिंह, अध्यक्ष राष्ट्रीय निर्माण पार्टी, नई दिल्ली, कुसुम बाला, सुमित्रा आर्य, सरोज आर्य, अरुणा देवड़ा एवं जयपुर की सभी आर्य समाजें जिनमें आर्य समाज राजापार्क, आर्य समाज मोती कटला, आर्य समाज मानसरोवर, महिला आर्य समाज मानसरोवर, आर्य समाज वैशाली नगर नींदड, आर्य समाज जनता कॉलोनी, आर्य समाज बगरू और वैदिक सत्संग मानसरोवर आदि सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ।

आर्य समाज किशनपोल के प्रधान ओम प्रकाश वर्मा एवं प्रतिष्ठित सभासद श्री कोशलाधीश मिश्रा का अभिनन्दन किया गया। आर्य समाज किशनपोल के चुनाव दिनांक 2 मार्च 2019 को सम्पन्न हुए। जिसमें सर्वसम्मति से ओम प्रकाश जी वर्मा को प्रधान मनोनीत किया गया एवं उन्होंने अपनी कार्यकारिणी का गठन किया जिसमें कार्यकारी प्रधान पुरुषोत्तम दास, उप प्रधान महेश शर्मा, मंत्री कमलेश शर्मा, कोषाध्यक्ष श्री हनुमान सहाय शर्मा, उप मंत्री शैलेश शाह आदि चुने गए।

॥ ओ३म् ॥
वेद प्रचार, विश्व शांति, राष्ट्रोत्थान एवं सम्पूर्ण क्रांति के लिये समर्पित पाक्षिक पत्र
आर्य नीति

प्रेषक : सत्यव्रत सामवेदी, सम्पादक, आर्य नीति
आर्य समाज, राजापार्क, जयपुर - 4
राजस्थान

पंजियन संख्या
RAJHIN(RNI)2000/2567
डाक पंजीयन संख्या
Jaipur City/264/2018-20

प्रेषित : ....

सत्यव्रत सामवेदी, सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक 5च-13, जवाहर नगर, जयपुर के लिये हरिहर प्रिन्टर्स, आदर्श नगर, जयपुर से मुद्रित।
सम्पादक मण्डल
घनश्यामधर त्रिपाठी
फोन नं. : 0141-2621859 का. : 2624951
M : 9829052697, e-mail: Vishwamaryam@gmail.com
9929804883 Vishwamaryam@rediffmail.com
आर्य समाज, विद्या समिति एवं शिक्षा समिति, आदर्श नगर, जयपुर के सौजन्य से प्रकाशित
-:: डाक वापसी का पता ::-
आर्य नीति, आर्य समाज, आदर्श नगर, जयपुर-4, राज.